कृषि क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश समस्या एवं सम्भावना

डॉ0 अनिल प्रताप सिंह
एसोसिएट प्रोफेसर वाणिज्य,
हरिश्चन्द्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय, वाराणसी

भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि तथा इससे सम्बद्ध क्षेत्र भारत की कुल जनसंख्या के 70 प्रतिशत की आजीविका का साधन है। भूख, दरिद्रता, गरीबी, कुपोषण, जनसंख्यावृद्धि एवं पर्यावरणीय असन्तुलन आदि से निपटने के लिये कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाना नितान्त आवश्यक है। विज्ञान और उद्योग जगत के सहयोग से कृषि क्षेत्र को एक नई विकास की गति प्रदान की जा सकती है। कृषि क्षेत्र को विकसित करने के लिये कृषि के क्षेत्र में अधिक निवेश की आवश्यकता है। राष्ट्रीय बचत इस कार्य के लिये पर्याप्त नहीं है, इसलिये कृषि क्षेत्र की वित्तीय माँग को पूरा करने के लिये प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की नितान्त आवश्यकता है। भारत सरकार अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की आवश्यकता को समझते हुये निरन्तर बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। कृषि भी उनमें से एक है। प्रस्तुत शोध पत्र में कृषि क्षेत्र में होने वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का अध्ययन किया गया है। साथ ही यह भी विश्लेषित करने का प्रयास किया गया है कि इस क्षेत्र को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने में किन–किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तथा इन समस्याओं का क्या समाधान हो सकता है।

भारत वर्ष जो कि प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण होते हुये भी अभी विकासशील देशों की श्रेणी में ही खड़ा है, क्योंकि हम संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं कर पा रहे हैं जिसका प्रमुख कारण है पूँजी का अभाव। ऐसी स्थिति में यदि भारत को विकसित देशों की श्रेणी में अपने को खड़ा करना है तो उसे भरपूर विदेशी निवेश को आमंत्रित करना होगा। वर्तमान में सरकार इस दिशा में अग्रसर भी है। विभिन्न क्षेत्रों में विदेशी निवेश की सीमा को बढ़ाया जा रहा है। 2015 की तुलना में 2016 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 18 प्रतिशत बढ़कर 46 अरब डालर पर पहुँच गया है। औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग (DIPP) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सेवा, दूरसंचार, व्यापार, कम्प्यूटर हार्डवेयर और साफ्टवेयर तथा आटोमोबाइल क्षेत्र में अधिक विदेशी पूँजी निवेश हुआ है।

कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है यहाँ की 60 प्रतिशत आबादी प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर ही आश्रित है और सकल घरेलू उत्पाद में इसकी 14 प्रतिशत की भागीदारी है। फिर भी यहाँ का किसान अपनी फसल को खेत में ही नष्ट करने के लिये मजबूर होता है, उसे अपनी फसल की उचित कीमत वसूल नहीं हो पाती है। भण्डारण की सुविधा से वंचित है तथा उपज को प्रसंस्करित करने के साधनों के अभाव से आज भी जूझ रहा है।

ऐसी स्थिति में यहाँ कृषि क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की भरपूर सम्भावना है। इसीलिये सरकार ने चुनिन्दा उत्पादों में जिसमें चाय भी शामिल है 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति प्रदान कर दी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी का मेक इन इण्डिया अभियान इसी पर आधारित है। भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार अप्रैल 2000 से सितम्बर 2015 तक के 15 वर्षों की अवधि में कृषि सहायक सेवाओं जिनमें हार्टीकल्चर, टिश्यूकल्चर, सेली कल्चर, बीज उत्पादन आदि में 179 करोड़ डालर का निवेश हुआ है जो कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का मात्र 0.67 प्रतिशत है। इसी अवधि में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में 255 करोड़ डालर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ जो कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का 2.47 प्रतिशत है। भारत सरकार ने निर्यात बढ़ने की सम्भावना को देखते हुये नवम्बर 2011 में कृषि क्षेत्र में बागवानी, फल एवं सब्जी उत्पादन, फूल उत्पादन मशरूम उत्पादन, रेशम उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, भण्डारण, कृषि सेवायें, कृषि यन्त्र, बीज, उर्वरक आदि के खुदरा व्यापार व विपणन एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दे दी है। इससे इनमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कई गुना बढ़ने एवं कृषि में नई प्रौद्योगिकी आने की सम्भावनाएं हैं। इससे कृषि के विकास के साथ–साथ ग्राम विकास की भी अच्छी सम्भावनाएं हैं जो कि गांधीजी का सपना था। मुझे यह विश्वास है कि

6,00,000 गाँवों में निवास कर रहे 700 मिलियन भारतीय पर कृषि क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा।

यह नितान्त आवश्यक है कि कृषि विकास को प्रोत्साहित करने के लिये कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ाया जाय जिससे गरीबी, भूखमरी, कुपोषण एवं पर्यावरण असन्तुलन का सामना किया जा सके। कृषि में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होने से कृषि प्रसंस्करण की सुविधा तथा भण्डारण की सुविधा का विकास होगा जिससे किसानों को अपने उत्पाद का उचित मूल्य प्राप्त होगा तथा किसानों के रहन–सहन का स्तर ऊँचा होगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। विभिन्न शोधों से यह स्पष्ट हो चुका है कि किसी भी देश के आर्थिक विकास में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था को अपनी विकास दर को 7 से 8 प्रतिशत करने के लिये अपनी जी.डी.पी. का 35 से 40 प्रतिशत निवेश करने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय बचत इस प्रतिशत को प्राप्त करने में सक्षम नहीं है इसलिये प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नितान्त आवश्यक हो गया है।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश :–

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वर्तमान में भारत में एक बहस का मुद्दा बना हुआ है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (I.M.F.) एवं आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (O.E.C.D.) ने एक देश से दूसरे देश के मध्य किसी देश के निवासी (Resident) द्वारा स्थिर रुचि के साथ किसी कारोबार में निवेश करने को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहा है। प्रत्यक्ष विदेशी पूँजी को विकास के उपकरण के रूप में देखा जा रहा है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश देश के विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देंगे, निर्यात को बढ़ायेंगे तथा आयात को कम करेंगे। तकनीकों एवं ज्ञान का स्थानान्तरण होगा, नई वस्तुओं का आविष्कार होगा तथा देश का भुगतान सन्तुलन अनुकूल होगा। इसलिये कृषि क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के द्वारा भारत की कृषि निश्चित रूप से उन्नत होगी, खाद्यान्न उत्पादन बढ़ेगा तथा प्रकृति पर निर्भरता को कम किया जा सकेगा। पिछले दशक से देखा जाय तो सभी विकासशील देशों ने कृषि क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया है। भारत जो कि एक तेजी के साथ विकास कर रहा देश है अतः यहाँ प्रत्यक्ष विदेशी निवेष की राह आसान हुई है। भारत ने पूरे विश्व के निवेशकों को आकर्षित किया है। विदेशी निवेशक दो प्रकार से विनियोग करके देश के विकास में योगदान करेंगे। पहला ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट और विलय एवं अधिग्रहण।

ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट :–

इसके अन्तर्गत एक विदेशी कम्पनी दूसरे देश में नये सिरे से व्यापार प्रारम्भ करेगी, नई फैक्ट्री या नये स्टोर का निर्माण करेगी अर्थात् पूर्ण रूप से स्वतन्त्र व्यापार करेगी।

विलय एवं अधिग्रहण :–

इसके अन्तर्गत देश में विद्यमान कम्पनियों का विदेशी कम्पनियों द्वारा अधिग्रहण कर लिया जायेगा या विदेशी कम्पनियाँ उनका विलय अपनी कम्पनी में कर लेंगी।

भारतीय कृषि में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की स्थिति

भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रोत्साहन एवं अनुमोदन के लिये औद्योगिक नीति एवं प्रोत्साहन विभाग की स्थापना 1995 में की गयी और इसे सन् 2000 में पुनः स्थापित किया गया। कुछ नियमों एवं शर्तों के साथ कृषि में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को स्वीकृति दी गयी जिनका विवरण निम्नलिखित है –

1. **कृषि एवं पशुपालन :–** कृषि एवं पशुपालन की क्रियाओं के अन्तर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अनुमति प्रदान की गयी–
   - **अ)** फूल उत्पादन, बागवानी तथा मशरूम एवं अन्य सब्जियाँ
   - **ब)** बीज एवं पौधरोपण सामग्री का उत्पादन एवं विकास
   - **स)** पशुपालन (कुत्तों के प्रजनन) एवं मछलीपालन
   - **द)** कृषि क्षेत्र से सम्बन्धित सेवाएँ
2. **चाय की बागवानी :–** चाय क्षेत्र की बागवानी को भी 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति प्रदान कर दी गयी है।

भारत परम्परागत रूप से कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था है। यहाँ की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता विकसित देशों की तुलना में बहुत कम है जिसका प्रमुख कारण है कृषि का पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर होना। किसान को आज भी वित्तीय सुविधाएँ प्राप्त नहीं हैं, उन्नत बीज, उर्वरक एवं कीटनाशकों की उपलब्धता उनको समय से नहीं हो पाती है। कृषि यन्त्रों एवं उपकरणों का भी अभाव बना हुआ है। किसानों को बिजली पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रही है, नहरों का पानी भी निरन्तर नहीं प्राप्त हो पाता है। ऐसे में देखना यह है कि ऐसी स्थिति में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भारत के लिये कितना उपयोगी सिद्ध होता है। यदि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सकारात्मक प्रभाव रहा तो निश्चित रूप से भारत की कृषि का विकास उन्नत देशों की बराबरी पर पहुँच जायेगा और कृषि निर्यात की स्थिति काफी सुदृढ़ हो जायेगी, किसान भूखों नहीं मरेगा उसे अपनी फसल की उचित कीमत प्राप्त होगी किसानों की खुशहाली के दिन आयेंगे किन्तु यह सभी बातें अभी भविष्य के गर्त में हैं।

भारतीय कृषि में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की चुनौतियाँ

विश्व बैंक द्वारा निर्धारित कृषि क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रमुख समस्यायें:–

1. बड़े स्तर की कृषि छूट भारतीय कृषि में निवेश को हतोत्साहित करती है।
2. कृषि पर बहुत अधिक नियमन होने के कारण लागत बढ़ती है, अनिश्चितता एवं मूल्य जोखिम भी बना रहता है।
3. भूमि, श्रम और उधार बाजार में सरकार का अत्यधिक हस्तक्षेप।
4. बुनियादी ढाँचे की कमी एवं सेवाओं का अभाव।

कृषि क्षेत्र के विकास में बहुत से अवरोधक तत्व हैं चाहे वह स्थानीय स्तर पर हों, राष्ट्रीय स्तर पर हों या अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हों जो कृषि निवेश को प्रभावित करते हैं। ये अवरोध निम्नलिखित हैं–

स्थानीय स्तर पर :–

1. बुनियादी ढाँचा का अभाव
2. प्राकृतिक संसाधनों का सदउपयोग नहीं
3. निम्न कृषि उत्पादकता
4. कृषि आ–दाओं की उपलब्धता में कमी
5. संसाधन वितरण (भूमि–जल) की उपर्याप्तता।

राष्ट्रीय स्तर पर :–

1. राजनीतिक अस्थिरता
2. आर्थिक स्थिरता की समस्या
3. नियामक संस्थाओं का अभाव
4. वित्तीय संसाधन की कमी
5. नियोजन एवं विकास के खाके की कमी
6. लालफीता शाही।

क्षेत्रीय स्तर पर :–

1. आपसी जल विवाद
2. परिवहन ढाँचे का अभाव

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ाने के उपाय :–

सरकार कृषि में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिये बहुत से उपाय कर रही है। कुछ प्रमुख कदम निम्नलिखित हैं:–

1. सरकार ने कोल्ड स्टोरेज, भण्डारण एवं बीज विकास के लिये 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी प्रदान की है।
2. दाल के उत्पादन को बढ़ाने के लिये 60,000 दाल गाँवों को प्रोत्साहित करने के लिये 65.1 मिलियन डालर के खर्च की व्यवस्था किया है।
3. कृषि साख की समुचित व्यवस्था की गयी है।
4. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की स्थापना की गयी है।

5. नाबार्ड द्वारा निजी क्षेत्र के लिये ऋण व्यवस्था प्रारम्भ की गयी है जिससे वे भण्डारण, कोल्ड स्टोरेज आदि के लिये ऋण प्राप्त कर सके।
6. हर्बल टी प्रोसेसिंग सुविधा की स्थापना के लिये प्रश्चिम बंगाल में 500 करोड़ की परियोजना प्रारम्भ की गयी है।

निष्कर्ष :–

कृषि क्षेत्र में बागवानी, पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन, मछली पालन, मशरूम एवं सब्जियाँ, कृषि यन्त्र एवं उपकरण, विपणन सेवा एवं भण्डारण सेवा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आने से कृषि के विकास के साथ–साथ ग्राम्य विकास की भी अच्छी सम्भावना है। सरकार ने खाद्य प्रशंस्करण उद्योग में नई प्रोद्योगिकी के महत्व को जानते हुये इसमें भी 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने का निर्णय लिया है। प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का भी बड़ा वैश्विक बाजार है। प्रारम्भ से सरकार की नीति थी कि किसान परिवारों के शिक्षित युवा सहकारी समिति बना कर खाद्य प्रशंस्करण क्षेत्र में आयें तथा अपने खेतों से अपने खाद्य प्रसंस्करण उद्यम का लिंकेज कर विपणन करे। किन्तु पढ़े–लिखे युवाओं में सहकारी समितियों के प्रति उदासीनता रही है। वे कम्पनी बनाकर और उसका सी.ई.ओ. बनकर नये उद्यम का स्टार्टअप करना अधिक पसन्द करते हैं। यदि वे कम्पनी बनाकर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में आतें हैं तो उनके उद्यम में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अच्छी सम्भावनाएँ रहेंगी। कुल मिलाकर सरकार द्वारा 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दिये जाने के निर्णय से कृषि में पूँजी निवेश के बढ़ने एवं उसके विकास की अच्छी सम्भावनाएँ हैं। कृषि प्रसंस्करण के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भारत के लिये लाभ का सौदा साबित हो सकता है। खाद्य सुरक्षा को बरकरार रखने के लिये कृषि क्षेत्र में नये अनुसंधानों और तकनीकों को पूरी शिद्धत के साथ बढ़ावा देना होगा। मौजूदा गरीबी, कुपोषण, जनसंख्या वृद्धि और पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियाँ गम्भीर होती जा रही हैं। इनसे निपटने के लिये कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाना नितान्त आवश्क है। विज्ञान और उद्योग जगत के सहयोग से कृषि क्षेत्र को एक नई ऊँचाई पर पहुँचाया जा सकता है। निश्चित रूप से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इस कार्य में अपनी अहम भूमिका निभायेगा।

References

1. Hallam ‘D’ 2009 foreing investment to Developing country-Agriculture Issues, policy Implications and International Response OECD Global forum on International Investment
2. Kumar Bipin (2012) FDI & Indian Agriculture : Recent trend
3. Roy J and Banerjee P. (2007) Attracting FDI from the Indian Diaspara : The way forward Confederation of Indian Industry
4. The Economic surrey 2016-2017
5. The Union Budget 2016-2017
6. http://unctad.org/en/publications library/wir 2016 en pdf.
7. Renuka R. ets, (2013) “Impact of FDI in Indian Economy with special reference to retail sector in India”. Global Research Analysis, volume : 2 issue 1 Jan 2013.
8. RBI (2012) Hand Book of Statistics on Indian Economy, http//www.rbi.org.in
9. https://dbie.rbi.org.in
10. www.mediafar rights.org in
11. www.Jagran.com